देश के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों में शामिल हुआ उप्र

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च रिपोर्ट में उप्र व गुजरात को बताया गया प्रसंस्करण का हब

राज्य, जागरण● लखनऊ: खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र उत्तर प्रदेश तेजी से एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में गुजरात और उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख प्रोसेसिंग केंद्रों के रूप में दर्शाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां गुजरात के मेहसाणा और बनासकांठा में आधुनिक डिहाइड्रेशन (निर्जलीकरण) संयंत्र विकसित हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा और फर्रुखाबाद में नए अत्याधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित हो रहे हैं। इनसे कांट्रैक्ट फार्मिंग और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क मजबूत हो रहा है और किसानों की आय भी बढ़ रही है।

खाद्य प्रसंस्करण को गति देने के लिए सरकार ने 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023' लागू की है। इसके तहत 19 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। उद्यमियों को उत्पादन-आधारित सब्सिडी, ब्याज सहायता सहित अन्य रियायतें दी जा रही हैं। सौर ऊर्जा, कोल्ड-चेन, क्लस्टर माडल और तकनीकी उन्नयन के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 65,000 से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां संचालित हैं, जिनसे करीब 2.55 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। सरकार का लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक हजार नई प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना है। राज्य में अब तक 15 से अधिक एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग पार्क विकसित किए गए हैं, इनमें बरेली, बाराबंकी, वाराणसी और गोरखपुर प्रमुख हैं। वहीं सरकार का फोकस अब फल-सब्जी प्रसंस्करण, उच्च मूल्य वाली फसलों और निर्यात-उन्मुख उद्योगों पर है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मिलेगी रफ्तार

राज्य, जागरण● लखनऊ: दीपावली के पहले शुरू हुई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) अब गति पकड़ने जा रही है। किसानों की आय और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए संचालित इस योजना में प्रदेश के 12 जिले चयनित किए गए हैं। अब इन जिलों में इसके क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन कर दिया गया है। यह समितियां स्थानीय जलवायु, परिस्थिति आदि के अनुसार योजनाएं तैयार कर काम कराएंगी। वहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति भी गठित की गई है जो योजना के लिए धन की उपलब्धता आदि की व्यवस्था करेगी।

12 12 जिले योजना में शामिल हैं, बढ़ाई जाएगी कृषि उत्पादकता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर को इस योजना का शुभारंभ किया था। इसके तहत उप्र में महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगढ़, श्रावस्ती और सोनभद्र को शामिल किया गया है। इन जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके लिए सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, पंचायत व ब्लाक स्तर पर भंडारण सुविधा, सिंचाई व्यवस्था, लघु व मध्यम किसानों के लिए ऋण सुविधा सुलभ कराने पर जोर रहेगा। प्रदेश सरकार इस योजना में अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन की कोशिश में जुटी है। संबंधित जिलों में डीएम की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय समिति गठित की गई हैं। कृषि, जिला पंचायत, उद्यान, मत्स्य, पशुधन आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों को समिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं राज्य स्तरीय समिति में भी कुल 17 सदस्य शामिल किए गए हैं। यह समिति चयनित जिलों में योजनाओं के लिए समय पर धनराशि जारी करना, विभागों के बीच समन्वय आदि सुनिश्चित करेगी। इन जिलों के उत्पादों के विपणन, ब्रांडिंग और मूल्यवर्धन में भी सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि निदेशक डा. पंकज त्रिपाठी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

25 दिनों में हुई 44 हजार टन धान की सरकारी खरीद

राज्य में फसलों की सरकारी खरीद की गति अभी तेज नहीं हो पाई है। 25 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44,127 टन धान की खरीद हुई है। वहीं धान बिक्री के लिए अब तक 1,54,035 किसानों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। पिछले वर्ष इस अवधि में 1,51,374 किसानों ने पंजीकरण कराया था। वहीं बाजरा के लिए 15248, ज्वार के लिए 2706 तथा मक्का के लिए 1509 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक पिछले वर्ष इस अवधि में 25,329 टन धान की खरीद हुई थी, इस हिसाब से इस बार अधिक खरीद हुई है। वहीं 4153 टन बाजरा की भी खरीद हो चुकी है।